

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2021—फाल्गुन 28, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक—भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2021

क्र. एफ 1(ए)19—2017—ब—2—दो.— राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)—2020—EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018—21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) परिवार सहित स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)—2020—EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील है।

क्र. एफ 1(ए)69—2013—ब—2—दो.— राज्य शासन, एतद्वारा, श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेन्ज, भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)—2020—EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018—21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2021

क्रमांक. एफ-3-41/2021/18-5 स0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 4974-विदिशा वि.यों 496/नग्नानि/2020 दिनांक 20/11/2020 द्वारा प्रकाशित विदिशा विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार विदिशा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में 19(1) में अनुमोदित किया गया है, तथा योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल
2. कलेक्टर, जिला विदिशा मध्य प्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय— विदिशा, मध्य प्रदेश
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद विदिशा

क्र	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात प्रावधान
1	<p>अध्याय-3</p> <p>3.10 बायपास मार्ग पर नियंत्रण</p> <p>“इन मार्गों के दोनों ओर 75-75 मीटर भूमि छोड़कर 200 मीटर गहराई तक निम्न गतिविधियां प्रस्तावित की जा सकती हैं।”</p>	<p>अध्याय-3</p> <p>3.10 बायपास मार्ग पर नियंत्रण</p> <p>इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात तथा इसके पश्चात मार्ग के दोनों तरफ 200-200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी। अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग अनुरूप मान्य होंगी। बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा।</p>
2	4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमन	

4.7.1 ले—आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन निम्नानुसार होंगे—
विदिशा : ले—आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन

क्र.	ले—आउट का न्यूनतम क्षेत्र (हे. मे.)	न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिशत मे.)	ऐमिनिटी के लिये न्यूनतम क्षेत्र यथा शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं (प्रतिशत)	स्थानीय सुविधाजनक दुकानें (प्रतिशत)	अधिकतम आवासीय भूखण्डीय क्षेत्र (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1	4.0 हे. या अधिक	10	8.0	2.0	50
2	3 हे. से 3. 99	12	6.5	1.5	50
3	2.0 हे. से 2. 99	13	6.0	1.0	50

टीप :— आवास एवं पर्यावरण नीति 2007 में समय—समय पर किये गये संशोधन मान्य होंगे।

विलोपित

- 3 4.20 बायपास मार्ग 'इस बायपास के दोनो ओर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र छोड़ते हुए इसके पश्चात् मार्ग के दोनो तरफ 200–200 मीटर तक निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार होंगी' —

4.20 बायपास मार्ग इस बायपास के दोनो ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200–200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी। अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी। बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा।

2	सारणी 4 सा 18 के सरल कमांक 4 कॉलम 4 में कलाकेन्द्र के पश्चात् निम्नानुसार अतः स्थापित किया जाता है :— सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
3	सारणी 4 सा 18 के सरल कमांक 7 कॉलम 4 में गौशाला के पश्चात् निम्नानुसार अतः स्थापित किया जाता है :— सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या —

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
 - ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
 - iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।
- टीप :— उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

विकास योजना में किया गया उपांत्तण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील—कसरावद,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश**

क्र. 29—भू—अर्जन—2020—21

कसरावद, दिनांक 06 जनवरी 2021

**प्ररूप- “ख”
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक- 22 अ-82/2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्घाहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील-कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला-खरगोनमध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	हतोला प.ह.न.-36	45	0.002
			130/2	0.011
			141/4	0.011
कुल योग			03	0.024

क्र. 171—भू—अर्जन—2020—21

कसरावद, दिनांक 25 जनवरी 2021

प्ररूप- “ख”
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- ०८ अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्धवन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-डाबरी तहसील-कसरावद एवं जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			352	0.009
			358/2	0.004
			358/1	0.006
			360	0.012
			364/5	0.002
			364/4	0.002
			365	0.001
			289/1/1	0.007
			290	0.001
			347/3	0.002
			347/2	0.006
			347/1	0.006
			346/1	0.005
			305	0.008
			38/1	0.008
			37	0.003
			346/2	0.005
			307/4	0.009
			306/1	0.005

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	डाबरी प.ह.न.-38	295	0.004
			22/2	0.005
			303/4	0.001
			303/3	0.006
			303/2	0.005
			303/1	0.009
			38/3/2	0.008
			24	0.003
			28/1	0.002
			31	0.002
			32/1	0.008
			65/3	0.008
			65/1	0.001
			65/8	0.008
			64/3	0.013
			69/1	0.010
			69/3	0.004
			71/1	0.008
			71/2	0.004
			72/1	0.002
			73/1/1	0.003
			73/1/2	0.001
			77/1/1	0.009
			76/1	0.004
			76/2	0.015
			289/1/2	0.005
			288	0.017
			281/1	0.009
			281/2	0.005
			281/3	0.002
			266	0.001
			270	0.007
			269	0.003
			229/1	0.003
			228/4	0.003
			228/2	0.006
			406/2	0.012
			407	0.002
			414/2	0.006
			419/1	0.005

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
खरगोन	कसरावद	डाबरी प.ह.न.-38	414/1	0.006		
			422/2	0.006		
			422/1	0.006		
			425/2	0.010		
			425/1	0.012		
			117	0.007		
			116	0.009		
			115/1	0.014		
			95/1	0.002		
			94/2	0.002		
			91/1	0.014		
			91/2/4	0.002		
			92/3	0.006		
			92/2	0.007		
			92/1	0.004		
कुल योग			287	0.007		
कुल योग			75	0.444		

संघ प्रिय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 389—भू—अर्जन—2021

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जनवरी 2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार ऐतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक—F-22/03/2017—18/ल.सि./31/1358 भोपाल, दिनांक 19/06/2018 की छायाप्रति संलग्न है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—6 (2) के अन्तर्गत “लघु सिंचाई योजना” बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा—6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा—11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांडुणा	ग्राम— कुकडीखापा, प०ह०न—64 ब.न.—47 रा.नि.मं. —पांडुणा	रक्बा—0.433 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू—अर्जन अधिकारी तहसील—पांडुणा जिला छिन्दवाड़ा	डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनूपपुर, दिनांक 2 फरवरी 2021

क्रमांक— 674/स्था./तीन-एक/2021 :: तहसील अनूपपुर अन्तर्गत फुनगा क्षेत्र की आम जनता को अपनी राजस्व एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु हो रही कठिनाईयो तथा जन प्रतिनिधियों की मांग पर मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-1-3/2015/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16 जनवरी 2015 के अनुसार कानून व्यवस्था तथा जन समस्याओं के सुचारू संपादन को दृष्टिगत रखते हुए फुनगा मे उप तहसील घोषित किया जाता है।

2/- उपरोक्त उप तहसील कार्यालय की स्थापना मे होने वाला आवश्यक व्यय, तहसील अनूपपुर द्वारा वहन किया जावेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर द्वारा उप तहसील कार्यालय के न्यायालयीन कार्य सम्बन्धी कार्य क्षेत्र का निर्धारण भौगोलिक एवं जन सुविधा की दृष्टि से सुनिश्चित किया जावेगा।

चन्द्रमोहन ठाकुर, कलेक्टर.

राजस्व निरीक्षक मण्डल फुनगा को उपतहसील का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव

वर्तमान तहसील					प्रस्तावित उपतहसील फुनगा में सम्मिलित राजस्व निरीक्षक मण्डल, पटवारी हल्का व ग्राम				
क्रम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का क्रमांक व नाम	सम्मिलित ग्राम	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का	ग्राम		
1	अनूपपुर	केल्हौरी	01-बकही	बकही	-	-	-		
2			02-बरगवां	बरगवां	-	-	-	-	
3			03-केल्हौरी	केल्हौरी	-	-	-	-	
4			04-देवरी	खोली	-	-	-	-	
5				देवरी	-	-	-	-	
6				05-देवहरा	देवहरा	-	-	-	-
7					सकोला	-	-	-	-
8				06-पटनाकला	पटनाकला	-	-	-	-
9					पटनाखुर्द	-	-	-	-
10				07-डोगराटोला	अमिलिहा	-	-	-	-
11			डोगराटोला	-	-	-	-		
12			तुम्मीवर	-	-	-	-		
13	सकरा	सकरा	08-खम्हरिया	खम्हरिया	-	-	-		
14				बरहाटोला	-	-	-	-	
15				भगहा	-	-	-	-	
16				09-धिरौल	धिरौल	-	-	-	-
17					बोइडिहा	-	-	-	-
18				10-चिल्हारी	चंदवार	-	-	-	-
19					चिल्हारी	-	-	-	-
20				11-चकेठी	चकेठी	-	-	-	-
21			सकरा	सकरा	12-मेडियारास	चचाई आबाद	-	-	-
22						चचाई वीरान	-	-	-
23		मेडियारास			-	-	-	-	
24		13-परसवार			परसवार	-	-	-	-
25					मौहरी	-	-	-	-
26		14-सकरा			छोरापटपर	-	-	-	-
27					निदावन	-	-	-	-
28					संकरा	-	-	-	-
29		15-औढेरा			अंकुवा	-	-	-	-
30					औढेरा	-	-	-	-
31			किरर	-	-	-	-		
32		16-जमुड़ी	बडहर	-	-	-	-		
33			जमुड़ी	-	-	-	-		
34			डिवापानी	-	-	-	-		
35			बैरीबांध	-	-	-	-		
36	लखनपुर	17-लखनपुर	अगरियानार	-	-	-	-		
37			पौड़ीखुर्द	-	-	-	-	-	
38		18-ताराडाड	लखनपुर	-	-	-	-		
39			कर्राटोला	-	-	-	-		
40			ताराडाड	-	-	-	-		

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 342—री—1—भू—अर्जन—2021—प्र.क्र.—अ—82—2020—21

मंदसौर, दिनांक 26 फरवरी 2021

(आपसी सहमति से भूमि क्रयनीति के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मंदसौर जिले में चौसला तालाब के वेस्ट वियर के पानी से भूमि मटेरियल द्वारा प्रभावित का खेत पर जाने के कारण के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृष्कवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है।

अतः भूमि—अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम चौसला (रामनगर)		तहसील – दलौदा		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है।		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	ग्राम चौसला (रामनगर)	0.24	—	0.24
		0.23	—	0.23

अनुसूची (2)

मंदसौर जिले में आने वाली निजी भूमि का विवरण :—

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित है,	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	कमलाबाई बेवा नाथुलाल , पुष्कर, श्यामलाल, सोहनबाई, ताराबाई, मुन्नाबाई, रेखाबाईपिता नाथुलाल गायरी निवासी चौसला (रामनगर)	27	0.47	0.24	—	0.24
		28	0.45	0.23	—	0.23
					योग —	0.47 है।

भूमि नक्शा व प्लान का अवलोकन भू—अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-2-8-2019-सात-शा.7-190

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2021

म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 कमांक 01 के परिशिष्ट 01 में उल्लेखित मुख्य शीर्ष "स" अंतर्गत शीर्ष- 153 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाता है :-

शीर्ष क्रमांक	मामलों का विवरण	अधिनियम	धारा	रखने की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
155	निक्षेपों की वापसी में व्यतिक्रम होने पर कार्यवाही	म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000	4	8 वर्ष

टिप्पणी:- मुख्य शीर्ष "स" के पश्चात् मुख्य शीर्ष "ड" प्रमाण पत्र संबंधी में शीर्ष क्रमांक 154 पूर्व से होने से मुख्य शीर्ष "स" में शीर्ष क्रमांक 153 के पश्चात् शीर्ष क्रमांक 155 जोड़ा गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 01-अ-82-2019-20

छतरपुर, दिनांक 8 मार्च 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्खस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला-	छतरपुर	ख. तहसील-	राजनगर
घ.	ग्राम-	सलैया	घ. लगभग क्षेत्रफल-	41.342 है.

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्र.	अर्जित रकवा (हे.)
1	2	3	4
1	अनंदी पिता खूबा लछिया देखिया बसंती नौनी बाई पारवती सरजू बाई पुत्री खूबा मु. कलिया बेवा खूबा कोटर सा. देह भूमि रक्षामी शासन से प्राप्त भूमि	2	1.736
		4/1	0.028
2	बुदेया कौंदर पुत्र भगवाना कौंदर जाति कौंदर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	4/2	0.809

प्र. क्र. 0004-आ-82-2020-21

चंकि राज्य शासन को इस वात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः गृणी-आर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) गयी धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला-	छतरपुर	ख. तहसील-	बक्सराहा
ग.	ग्राम-	सुनहरा	घ. लगभग क्षेत्रफल-	2.715 है।

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्र.	अर्जित रकवा (₹.)
1	2	3	4
1	प्रहलादसिंह तनय नन्हेसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	9	0.085
2	मोनिका पति ब्रजेश जाति विल्यरे पता सुनहरा भूमि स्वामी	10/1/1/2	0.017
3	गणेश पिता धनसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	10/1/2	0.030
4	कोमल पुत्र बन्दी जाति लोधी पता ग्राम सुनहरा	12/1	0.043
5	धनसींग तनय तुलई जाति लोधी शासकीय (शा. नं. 18 में)	18/1 19	0.003 0.067
6	केवलसिंह तनय मुरलीधर पुनियां, खरगी पिता मुरलीधर जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी शा. नं. 20 में	20 21	- 0.012
7	विन्दावन, धानसिंह पिता मुलु जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	22 174	0.057 0.095
8	अनुद्धी तनय दरौवा जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	23	0.048
9	गनेशसिंह तनय धनसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	24	0.091
10	नेपाल सिंह तनय गुलझार उर्फ चतुर सिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	38 175	0.097 0.079
11	सिया रानी वेवा माधौसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	140 141	0.004 0.001
12	मुत्रा तनय पंचमु, तिजिया वेवा पंचू 1/2 चिट्ठू पिता भूरे रूपसिंग मानसींग पिता सिल्ली सुहदा उत्तरा पुत्री सिल्ली जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	153 319	0.025 0.082
13	धरम सिंह तनय छुट्टन सिंह ठाकुर पता सा. देह भूमि स्वामी	154/1	0.019
14	मन्दिर श्री श्री 108 राम- लाला जी मन्दिर पुजारी रामनाथ तनय सुखननुदन जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	154/2	0.022
15	उज्जन तनय लटकू जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	155	0.059
16	ज्योती सिंह पत्नी धरमसिंह ठाकुर पता निवासी ग्राम	156	0.065
17	हिम्मत तनय बारेलाल जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	158 172	0.003 0.048
18	परमलाल तनय हेमराज जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	159 166 168 169 170	0.020 0.079 0.010 0.017 0.011
19	सुजीवकुमार पिता धाग्गलाल सोनी पता निवासी बक्सराहा भूमि स्वामी	160	0.045

प्र. क्र. -0003-अ-82-2020-21

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला—	छतरपुर	ख. तहसील—	बकस्याहा
ग.	ग्राम—	बकस्याहा	घ. लगभग क्षेत्रफल—	0.055 है।

स.क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्रं.	अर्जित रकवा (ह.)
1	2	3	4
1	खुमान तनय दयाल लोधी जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	59/1	0.055
	कुल योग (ह.)	01 किता	0.055

2. गढ़ीसेमरा तालाब परियोजना की नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—सेवढ़ा
- (ग) ग्राम—डिरौलीडांग
- (घ) क्षेत्रफल—1.540 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
35/2	0.400	0.060
35/3	0.400	0.050
35/4	0.400	0.050
37	0.930	0.180
38/2	0.320	0.150
40/2	0.320	0.040
40/3	0.800	0.040
40/4	0.800	0.030
41/2	0.480	0.250
46	0.200	0.030
47	0.080	0.010
49	0.400	0.080
50/2	0.200	0.100
155	1.180	0.080
156	1.210	0.240
157	0.400	0.050
158	0.810	0.070
160	1.000	0.030
योग . .	<u>10.330</u>	<u>1.540</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच रोड के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 8 दिसम्बर 2020

क्र. 6804-कले.-रीडर-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की वैफल फायरिंग रेन्ज के निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है। Field Firing And Artillery Practice Act, 1938 के नियम 9 उपधारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला का नाम—बालाघाट
- (ख) तहसील का नाम—किरनापुर
- (ग) ग्राम का नाम—जानवा, पटवारी हल्का नं.-15, रा.नि.मंडल-किरनापुर.
- (घ) क्षेत्रफल—130X60=7380 वर्गफुट.

खसरा नंबर	रकबा में से रकबा (हे. में) (वर्गफुट)	अवधि (4)
(1)	(2)	(3)
67, 68/1, 223, 280	0.202, 7380	तीन वर्ष
	6.535,	
	13.160,	
	0.660	

(2) प्रयोजन—वैफल फायरिंग रेन्ज निर्माण कार्य हेतु.

(3) अनुमोदित नक्शा पत्र में संलग्न है.

(4) नक्शा का निरीक्षण कलेक्टर, न्यायालय एवं कार्यालय कमाण्डेंट कोबरा बटालियन जिला आरक्षित पुलिस लाईन बालाघाट में किया जा सकता है.

अधिसूचना प्रकाशन को जाने के दो माह के बाद उक्त कार्य किये जाने की पात्रता होगी.

दीपक आर्य, कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 4th March 2021

No. C-704-1-7-3-2020(Part-I).—In partial modification to the Registry Notification No. D-4763-1-7-3-2020, (Part-I), dated 11th November 2020, it is hereby declared that 05th March 2021 (Friday) shall be a non Court working day for the High Court of Madhya Pradesh Main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior. In lieu of the same, 25th September, 2021 (Saturday) is declared as a Court working day for the High Court of Madhya Pradesh Main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior.

By orders of Hon'ble the Chief Justice,

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 26 फरवरी 2021

क्र. D-894-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री कृष्णकांत शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	. . 225
अद्वैतन अवकाश	. . 75

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अद्वैतनिक अवकाश=————— X 75
के एवज में नगद 30
भुगतान.

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी 2021

क्र. A-668-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री कृष्ण कुमार सिंघई, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री सिंघई को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:—

1. अर्जित अवकाश . . 210

अद्वैतन अवकाश . . 90

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=210 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अद्वैतनिक अवकाश=————— X 90
के एवज में नगद 30
भुगतान.

क्र. A-670-दो-2-32-2018.—श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार (J-II) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 19 फरवरी 2021 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार (J-II), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (J-II) के पद पर कार्यरत रहते.

